इजराइल में विकट भविष्य

लेखक-सुकुमार मुरलीधरन (प्रोफेसर,ओ.पी. जिंदल ग्लोबल यूनिवर्सिटी, सोनीपत)

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II (अंतर्राष्ट्रीय संबंध)

द हिन्दू

13 अप्रैल, 2019

भ्रष्टाचार के आरोपों पर आसन्न आपराधिक अभियोग के साथ, इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने 9 अप्रैल को हुए आम चुनावों में नेसेट (इजरायली संसद) में लगातार चौथी जीत हासिल कर ली है। केंद्रीय चुनाव समिति के प्रमुख जज हनान मेलर के अनुसार, प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू की लिकुड पार्टी को सबसे ज्यादा 36 सीटें मिली हैं। जबकि मुख्य प्रतिद्वंद्वी ब्लू एंड ह्वाइट पार्टी के खाते में 35 सीटें आईं। लेकिन नेतन्याहू के लिए इस बार मुश्किलें पहले से काफी अलग हैं।

समर्थन के स्त्रोतः-

वैश्विक राय पर हासिल की गईं दो उल्लेखनीय जीतों ने श्री नेतन्याहू की जीत को आसान बनाया है। इन्हें हासिल करने में, उन्होंने यू.एस. में डोनाल्ड ट्रम्प प्रशासन के निर्विवाद समर्थन पर भरोसा किया।

इजराइल के भीतर श्री नेतन्याहू के विरोधियों का कहना है कि श्री ट्रम्प ने अभियान के बाद के दिनों में एक फरमान के साथ प्रभावी रूप से उनके लिए एक प्रचार वीडियो बनाया था, जिसमें गोलन हाइट्स पर इजराइल के अधिकार को मान्यता दी गयी थी। इसके बाद पिछले साल इजराइल के गठन की 70वीं वर्षगाँठ पर श्री ट्रम्प ने भेंट स्वरूप अमेरिकी दूतावास को तेल अवीव से येरूशलेम स्थानांतरित कर दिया था।

निष्क्रिय शांति प्रक्रिया, जो कि अरब दुनिया में सहयोगियों के गठबंधन को बनाए रखने के लिए अमेरिका को सक्षम करने वाले एक साथी से अधिक कभी नहीं रहा, को तब मृत घोषित कर दिया गया था। यहाँ तक कि महमूद अब्बास, आमतौर पर परिचित फिलिस्तीनी प्राधिकरण के अध्यक्ष, ने सभी प्रस्तावों को बातचीत से फिर से शुरू करने से इनकार कर दिया है।

जुलाई, 2018 में, नेसेट ने एक बुनियादी कानून बनाया, जिसमें इजराइल को यहूदी लोगों का राष्ट्र-राज्य घोषित किया गया। येरूशलेम इसकी अविभाज्य राजधानी और हिब्रू इसकी भाषा होगी। इजराइल देश के भीतर आत्मनिर्णय का अधिकार कानून यहूदी लोगों के लिए अद्वितीय होगा।

यह एक ऐसा कानून है जो इजराइल के 1.26 मिलियन फिलिस्तीनी नागरिकों की स्थिति और वेस्ट बैंक और गाजा में रहने वाले अनुमानित 5 मिलियन को एक स्थायी जेल में डालता है। यह 2007 में शुरू हुए एक प्रयास के अंतिम परिणाम को चिह्नित करता है, जब अमेरिका ने इराक के आक्रमण के साथ शुरू हुई क्षेत्रीय रणनीतिक वास्तुकला को फिर से बेहतर करने के सभी प्रयासों के बाद एक शांति दूत के रूप में प्रयास को फिर से शुरू कर दिया था, जहाँ वह असफल हो गया था।

कॉन्डोलीजा राइस, जो उस समय राज्य की सचिव थीं, ने वार्ता में वापस आने के लिए अपने इजराइली समकक्ष तजिपी लिवनी द्वारा निर्धारित पूर्व शर्त को गलत ठहराया था। सुश्री लिवनी ने जोर देकर कहा कि किसी भी परिस्थिति में शांति समझौते के द्वारा फिलिस्तीनी शरणार्थियों को उनके घरों में लौटने के संदर्भ में कोई रियायत देना, इजराइल के यहूदी चरित्र के लिए एक घातक खतरा होगा।

देखा जाये, तो 2008 में जॉर्ज डब्ल्यू बुश प्रशासन के इतिहास में गायब हो जाने के बाद,बराक ओबामा ने इजराइल से जातीय मुद्दे को अलग करने की मांग की थी। लेकिन, वर्तमान में ईरान के साथ परमाणु समझौते को तोड़ने के बाद श्री ट्रम्प ने अन्य कदमों को भी उलट दिया है, जो उनके पूर्ववर्तियों ने बल के बजाय सुलह के माध्यम से सत्ता की एक नई क्षेत्रीय वास्तुकला बनाने के लिए उठाए थे।

मजबूत अभियानः-

राजनीति में पदार्पण के बाद से श्री नेतन्याहू की अभियान संबंधी बयानबाजी को अक्सर फिलिस्तीनियों के खिलाफ भड़काने

के लिए कहा जाता था। इस बार इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अगर वह दोबारा निर्वाचित होकर आते हैं तो वेस्ट बैंक में यहूदी बस्तियों को अपने कब्जे में करेंगे। उन्होंने नेसेट के सहयोगियों को भी यह बताया कि जॉर्डन नदी और भूमध्यसागर के बीच के पूरे क्षेत्र को नियंत्रित करना 'भविष्य के लिए महत्वपूर्ण' साबित होगा।

इजराइल की सेना ने गाजा की सेना के साथ क्रूरता के साथ व्यवहार किया था, जिसमें लगभग 300 लोग मारे गए थे, जिनमें बच्चे और चिकित्सा-सहायक शामिल थे। एक जाँच के बाद, संयुक्त राष्ट्र के एक आयोग ने अंतर्राष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन के एक पैटर्न की पहचान की थी और गाजा में इजराइल के कार्यों के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ व्यक्तिगत प्रतिबंधों का आग्रह किया था।

भारत का दृश्य:-

भारत इजराइल के सैन्य-औद्योगिक परिसर के सबसे बड़े विदेशी संरक्षकों में शामिल है। वर्तमान में, इजराइल को एक आदर्श मॉडल के रूप में चित्रित किया गया है। फिलिस्तीन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता के नवीकरण के लिए राजनीतिक जीवन में असहिष्णुता की बढ़ती भावनाओं और धर्मनिरपेक्ष लोकतंत्र के ताने-बाने की छींटाकशी के खिलाफ लड़ने के साथ समवर्ती रूप से चलना चाहिए।

GS World टीम...

इजरायल-फिलिस्तीन विवाद

चर्चा में क्यों?

- इजराइल में बेंजामिन नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन ने आम चुनाव में जीत हासिल कर ली है और नेतन्याहू फिर से इजराइल के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं।
- इस बार प्रधानमंत्री बनने पर नेतन्याहू इजराइल में सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने का रिकॉर्ड बनाएंगे।
- वे रिकॉर्ड पांचवीं बार इजराइल के प्रधानमंत्री बनेंगे।
- चुनावी अभियान में बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा था कि अगर वह फिर से सत्ता में आते हैं तो कब्जे वाले वेस्ट बैंक में बसी यहूदी बस्तियों को इजराइल में मिलाएंगे। जिसके बाद से इजरायइल-फिलिस्तीन विवाद फिर से चर्चा में आ गया है।

क्या है विवाद?

- गाजा पट्टी एक छोटा सा फिलिस्तीनी क्षेत्र है, यह मिस्र और इजराइल के मध्य भूमध्यसागरीय तट पर स्थित है।
- फिलिस्तीन अरबी और बहुसंख्यक मुस्लिम बहुल इलाका है। इस पर 'हमास' द्वारा शासन किया जाता है जो इजराइल विरोधी आतंकवादी समूह है। वो इसलिए क्योंकि फिलिस्तीन और कई अन्य मुस्लिम देश इजराइल को यहूदी राज्य के रूप में मानने से इन्कार करते हैं।
- 1947 के बाद जब UN ने फिलिस्तीन को एक यहूदी और एक अरब राज्य में बाँट दिया था जिसके बाद से फिलिस्तीन और इजराइल के बीच संघर्ष जारी है जिसमें एक अहम मुद्दा यहूदी राज्य के रूप में स्वीकार करना है, तो दूसरा, गाजा पट्टी है जो इजराइल की स्थापना के समय से ही इजराइल और दूसरे अरब देशों के बीच संघर्ष का कारण साबित हुआ है।
- जून, 1967 में जब दूसरी जंग हुई, तो 6 दिनों तक चली, जिसमें इजराइल ने फिर से गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया।
- इजराइल का यह कब्जा 25 सालों तक चला, लेकिन दिसंबर, 1987 में गाजा के फिलिस्तीनियों के बीच दंगों और हिंसक झड़प के कारण और इजराइली सैनिकों पर कब्जा करने से एक विद्रोह का रूप दे दिया।
- 1994 में इजराइल ने इजराइल और फिलिस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन (पीएलओ) द्वारा हस्ताक्षरित ओस्लो समझौते की शर्तों के तहत फिलिस्तीनी अथॉरिटी (पीए) को गाजा पट्टी में सरकारी प्राधिकरण का चरणबद्ध स्थानांतरण शुरू किया था।

मुख्य बिंदु

- साल 2000 की शुरूआत में, पीए और इजरायल के बीच वार्ता

नाकाम होने के कारण हिंसा अपने चरम रूप में पहुंच गयी जिसे खत्म करने के रूप एवज में इजराइल के प्रधानमंत्री एरियल शेरोन ने 2003 के अंत में एक योजना की घोषणा की थी, जो गाजा पट्टी से इजराइल सैनिकों को वापस हटने और स्थानीय निवासियों को बसाने पर केंद्रित है।

- सितंबर, 2005 में इजराइल ने क्षेत्र से पलायन पूरा कर लिया और गाजा पट्टी पर नियंत्रण को पीए में स्थानांतरित कर दिया गया था। हालांकि, इजराइल ने इसके क्षेत्ररक्षण और हवाईगश्त को जारी रखा।
- जून, 2007 में हमास ने एक बार फिर गाजा पट्टी पर कब्जा कर लिया और फतह (फिलिस्तीन राजनीतिक समूह) की अगुवाई वाली आपातकालीन कैबिनेट ने पश्चिम बैंक पर कब्जा कर लिया था।
- फिलिस्तीनी अथॉरिटी अध्यक्ष महमूद अब्बास ने घोषणा की जिसमें कहा गया गया कि गाजा हमास के नियंत्रण में रहेगा।
- 2007 के अंत में इजराइल ने गाजा पट्टी को दुश्मन क्षेत्र घोषित कर दिया और इसके साथ ही गाजा पर कई प्रतिबंधों को मंजूरी दी, जिसमें बिजली कटौती, भारी प्रतिबंधित आयात और सीमा को बंद करना शामिल था।
- जनवरी, 2008 में हुए हमलों के बाद गाजा पर इन प्रतिबंधों को और बढ़ा दिया गया और इसके अलावा पूरी तरह से गाजा पट्टी के साथ अपनी सीमा को सील कर दिया, ताकि अस्थायी रूप से ईंधन आयात को रोका जा सके। इसके बाद हमास की सेना ने गाजा पट्टी-मिस्र की सीमा के साथ ध्वस्त कर दिया जिससे नाकाबंदी के कारण उसे अन्न, ईंधन और सामान उपलब्ध करने के लिए हजारों गजान मिस्र में पहुंच गए।
- इसके बाद यूरोपियन यूनियन के पीछे हटने और सहमति के बाद गाजा पट्टी को चारों तरफ से सील कर गया।

संभावित प्रश्न (प्रारंभिक परीक्षा)

1. 'गाजा पट्टी' के सन्दर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए:-
   1. यह इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवादित क्षेत्र है।
   2. यह लाल सागर का तटीय द्वीपीय क्षेत्र है।
   3. यह इजराइल और सीरिया के मध्य विवादित क्षेत्र है।

   उपर्युक्त में से कौन-सा/से कथन सत्य है/हैं?
   (a) केवल 1
   (b) केवल 2
   (c) केवल 3
   (d) उपर्युक्त सभी

1. Consider the following statements regarding Gaja Strip-

1. It is the disputed region between Israel and Palestine.
2. It is the coastal island of red sea.
3. It is the disputed region between Israel and Syria.

Which of the above statements is/are correct?
(a) Only 1
(b) Only 2
(c) Only 3
(d) All of the above

संभावित प्रश्न (मुख्य परीक्षा)

प्रश्नः- इजराइल और फिलिस्तीन के मध्य विवादित मुद्दे को रेखांकित करते हुए बातइए कि भारत को इस मुद्दे पर किस प्रकार का दृष्टिकोण अपनाने पर बल देना चाहिए? चर्चा कीजिए।

(250 शब्द)

Q. Underlining the disputed matter between Israel and Palestine, elucidate what type of viewpoint should India adopt towards this matter. Discuss.

(250 Words)

नोट : 12 अप्रैल को दिए गए प्रारंभिक परीक्षा (संभावित प्रश्न) का उत्तर 1(b) होगा।